



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 76] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 1992/माघ 9, 1913
No. 76] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 1992/MAGHA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन संरक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1992

पर्यावरण अनादित्त कर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की
धारा 3(1) और धारा 3(2)(V) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम,
1986 के नियम 5(3)(क) के अर्धीत

का.घा. 83(घ).--अत्यधिक मृदा कटाव और कतिपय विकासात्मक
क्रियाकलापों के कारण जल और धातु प्रदूषण में पर्यावरण की पर्याप्तता
के कारण पर्याप्त प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव पारित हुआ है, जिससे
केवल प्राकृतिक स्रोतों जैसे जंगल, कठक वनस्पति, भ्राष्ट्र भूमि, मरिचो,
झीलों, जैनी पुष्प आरक्षितियों और वनस्पति सुरक्षा के विनाश को संकट
पैदा हुआ है, जो देश के बड़े भागों में तेजा से महत्व खो रहे हैं, बल्कि
उससे जीव मात्र पशु और मानव दोनों के स्वास्थ्य और आरक्षणिता
पर भी प्रभाव पड़ रहा है,

और यह आवश्यक है कि प्राकृतिक स्रोतों पर जीव समुदाय के
विकास के साथ ही वायु, जल और मृदा के प्रदूषण पर जोड़ना गहरा
है कि हमारे प्राकृतिक, जैविक और आनुवंशिक सम्पत्ति को सम्भार खतरा

हो गया है, नियंत्रण करके पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और उसकी
स्वातिथी को सुधारा जाए;

और कतिपय विकास परियोजनाएं प्रतिध्वनि पद्धति से परिभाषित
दूरियों से परे ध्यायमंगल अवस्थाति में प्रतिध्वनि पद्धति की बहुत क्षमता
के भीतर चलाई जानी चाहिए, जो अन्यथा प्रतिकूल के अधीन जाएगी,
जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासात्मक कार्यक्रमों पर
पर्यावरण और उसके विकास के साथ तात्प्रेम रखते हुए किए जाते हैं;

और पूर्वोक्त उद्देश्य प्रत्येक परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण
और परियोजना के प्रारम्भ से ही प्रतिकूल प्रभाव के निवारण, क्षीयन
या न्यूनीकरण के लिए आवश्यक पर्यावरण प्रबंध योजना के आधार पर
किसी क्षेत्र में अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी परियोजना
के सावधानीपूर्वक निर्धारण द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(1986 का 29) का धारा 3 का उपधारा (1) और उपधारा (2) के
खण्ड (5) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशित करती है
कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3)
के खण्ड (घ) के अर्धीत इस अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तारीख

से ही अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी नई परियोजना, विद्यमान उद्योग या परियोजना का विस्तारण या प्राधुनिकीकरण भारत के किसी भी भाग में हाथ में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न अनुमति कर दी गई हो।

2. अनुसूची 2 में अन्तर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी प्रारंभित जंगलों या अतिरिक्त परिस्थितिक रूप से सुग्राही क्षेत्र की सीमा के दस किलोमीटर के भीतर भूभाग राष्ट्रीय उद्यान या शरण स्थान की सीमा के 25 किलोमीटर के भीतर अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्थापित किसी परियोजना को केन्द्रीय सरकार से पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की आवश्यकता होगी।

3. अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में अन्तर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय किसी राज्य सरकार द्वारा किसी परियोजना को दी गई पर्यावरण संबंधी अनापत्ति का पुनर्विनीकरण कर सकेगा यदि—

(क) उस मंत्रालय को प्रभावित पक्षकारों से ऐसी अनापत्ति के विरुद्ध कोई लिखित अप्रभावित प्राप्त होता है, या

(ख) यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उस मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय संबंधी प्राप्तापत्तियों और अभियन्तों की संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी अनापत्ति देते समय अवहेलना की गई है।

4. परियोजना की पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :— (1) कोई व्यक्ति जो भारत के किसी भाग में किसी परियोजना को भूभाग अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी विद्यमान उद्योग या परियोजना के विस्तारण या प्राधुनिकीकरण को हाथ में लेना चाहता है, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली, को जहाँ पर्यावरण संबंधी अनापत्ति केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित है, या संबंधित राज्य सरकार के पर्यावरण सचिव को, जहाँ राज्य सरकार से पर्यावरण संबंधी अनापत्ति अपेक्षित है, एक आवेदन भेजेगा। यह आवेदन इस अधिसूचना से संलग्न प्रोफार्मा (उपबंध) में किया जाएगा और उसके साथ परियोजना की ब्योरेवार रिपोर्ट होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए भाग्यपूर्ण सिद्धान्तों के अनुसार तैयार की गई पर्यावरण प्रबंध योजना होगी।

(2) निम्नलिखित स्थल विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की रक्षा में—

(क) जंगल;

(ख) पिट हैबः उद्योग-शक्ति केन्द्र;

(ग) हाथों जल विद्युत शक्ति परियोजना; और

(घ) बहु उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना,

केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय से वेनों का काटना, किसी भी प्रकार का अस्थायी या स्थायी वेधन, बोटिंग या सस्तिर्माण अन्तर्निष्ठ करने वाला कोई अन्वेषण प्रारम्भ करने से पूर्व प्रारम्भिक स्थल संबंधी अनापत्ति अपेक्षित होगी।

उक्त स्थल संबंधी अनापत्ति मंजूर की गई क्षमता के लिए अनुमति की जाएगी और सस्तिर्माण प्रारम्भ करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमाम्य होगी।

(III) (क) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट का, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रभाव निर्धारण अधिकरण द्वारा, इस अधिसूचना की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट संरचना वाली विशेषज्ञ समिति के परामर्श से मूल्यांकन और निर्धारण किया जाएगा।

(ख) उक्त विशेषज्ञ समिति को परियोजना से संबंधित संक्रियाओं के प्रारम्भ से पूर्व, उनके दौरान या उनके पश्चात् किसी समय, यथास्थिति, स्थल या कारखाना परिसरों में प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ग) प्रभाव निर्धारण अधिकरण दस्तावेजों के तकनीकी निर्धारण और परियोजना अधिकारियों द्वारा किए गए आंकड़ों, जो स्थल भूभाग कारखाने में की गई यात्राओं के दौरान संगृहीत आंकड़ों द्वारा अनुपूरित होंगे। प्रभावित जनसंख्या और पर्यावरण संबंधी समूहों की अन्तः किया पर आधारित सिफारिशें तैयार करेगा। वे सिफारिशें और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। निर्धारण अपेक्षित दस्तावेजों की और परियोजना प्राधिकारियों से आंकड़ों की प्राप्ति पर तीन मास की कालावधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(IV) संबंधित प्रभाव निर्धारण अधिकरण को सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन और उन शर्तों को, जिनके अधीन पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, मानित करने के लिए संबंधित परियोजना प्राधिकारी संबंधित अधिकरण को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5. इस अधिसूचना में अन्तर्निष्ठ प्रस्थापित निर्देशों के विरुद्ध कोई आपत्ति फाइल करने में हितबद्ध कोई व्यक्ति लिखित रूप में सचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स, नवी रोड, नई दिल्ली के पास राजपथ में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर फाइल कर सकेगा।

[सं. जेड-12013/4/89-आई ए-1]

भारत. रजिस्ट्रार, सचिव (ई और एफ)

अनुसूची 1

केन्द्रीय सरकार से पर्यावरणीय निर्वाहन की अपेक्षा रखने वाली परियोजनाओं की सूची

1. परमाणु शक्ति
2. तापीय शक्ति
3. बहु उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं
4. पत्तन, बंदरगाह और विमानपत्तन
5. रेल पथ (जिसमें गैर रेल पथ भूमि का ध्वजन भी सम्मिलित है)
6. परिष्करण
7. उर्वरक
8. नाशक औद्योगिक और कौटुम्बिक
9. पैट्रोसायन

10. बिस्फोटक और उपसाधन
11. औषधि और औषधि निर्माण (बिनिमित्त के सिवाए)
12. प्लास्टिक उत्पादन
13. रबड़ संश्लिष्ट
14. एस्बेस्टास और एस्बेस्टास उत्पाद
15. सोडियम और पोटेशियम साइनाइड
16. प्राथमिक धातुकर्मीय उद्योग (जस्ता, सीसा, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात)
17. एकीकृत इस्पात संयंत्र
18. दूध, जीप, बार और अन्य भारी यानों के टायर/ट्यूब
19. क्षार (एन ए ओ एच)
20. एकीकृत पेंट कामप्लेक्स
21. मानव मित्त फाइबर (संश्लिष्ट और अश्लिष्ट, रेयान, नायलोन और पालिएस्टर)
22. सीसा प्रक्रमण सहित भंडारण बैट्री।
23. परिसंक्रमण अपशिष्ट और क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन के लिए भस्मीकरण संयंत्र
24. अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट से ऊपर ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक मानदंड।

अनुसूची 2

राज्य सरकार ने पर्यावरणीय निर्बाधन की अपेक्षा रखने वाली परियोजनाओं की सूची

(आवृत्तियों के पैरा 2 के उपबंधों के अन्वये रखते हुए)

परियोजना की प्रकृति

प्रारंभिक मापदंड (यदि कोई हों)

1. मृत्तिका शिल्प
2. कोयला प्रचालक
3. दुर्घटिकाकरण
4. कार्बनिक संयंत्र
5. इंजीनियरी (नलिका, संयंत्र, रोलिंग मिल)
6. उच्चताप स्रु
7. पाइप वेय (आर सी सी, इस्पात, सीकनहीन)
8. कैल्शियम कार्बाइड
9. कार्बन ब्लैक
10. स्नेहक सेल
11. कांच
12. औषधि और औषधि निर्माण (बिनिमित्त)
13. विद्युत सेपन
14. भंडारण बैट्री (गैर सीसा प्रक्रमण)
15. क्षार (एन ए 2, सी ओ 3 और सी ए सी ओ 3)
16. प्लास्टिक प्रक्रमण (एच बी पी ई, एल एल बी पी ई-एल बी पी ई, पी बी सी, पी पी आदि)
17. दोषहिया और साइकिल रिक्शा का टायर/ट्यूब।
18. सभी प्रकार के टायरों का निर्वातन।
19. पेंट (बार्निश, आर्कोल रसायन, वर्णक)
20. रंजक इकाई उद्योग
21. नायून और अपमार्जक
22. खाद्य प्रसंस्करण (मांस, मछली, प्राणिज्य उत्पाद)
23. वृक्ष प्रसंस्करण
24. कामज उत्पाद
25. गैर परिसंक्रमण अपशिष्टों के लिए भस्मीकरण संयंत्र।

26. जल विद्युत शक्ति	उत्पादन क्षमता
(क) सई परियोजनाएं	10 मेगावाट तक
(ख) विद्यमान नहर या बिजलीघर बांध पर पहले से ही अस्त.स्थापित पेनस्टॉक सहित सभी विद्युत गृहों का पला लगाया।	10 मेगावाट तक
27. सीमेंट	200 टन प्रतिदिन तक
29. इस्पात संयंत्र	50,000 टन पी. ए. तक
29. धमड़ा चर्मशोधन	5,000 खाल प्रतिदिन तक
30. आसबन	150 किलोमीटर प्रतिदिन तक
31. चीनी	1000 टन प्रतिदिन गन्ना तक
32. टेक्सटाइल	500 मीटर प्रतिदिन तक
33. लुगदी, कागज और अखबारी कागज	33,000 टन प्रतिदिन तक
34. रंजक माह्दयम	5 टन प्रतिदिन तक
35. ताप दूढ़, फीनोल और यूरिया फार्मल्डीहाइड	5000 टन प्रतिदिन तक
36. धमन	500 टन प्रतिदिन तक
37. दलस्यति मेस प्रसंस्करण	500 टन प्रतिदिन तक
38. ढलाई	रूप 20 करोड़ तक
39. संचार	रूप 20 करोड़ तक
40. समुद्र से एक किलोमीटर की ऊंचाई की समुद्र या 10000 मीटर की ऊंचाई के भीतर पर्यटन और अन्य परियोजनाएं।	रूप 5 करोड़ तक
41. सिंघाई	2000 हेक्टर कमांड क्षेत्र तक
42. खनन	5 हेक्टर पट्टा तक
43. सड़के (हिमालय और उत्तरी वन भूमि में)	5 किलोमीटर लंबाई तक
44. औद्योगिक सम्यदा	100 यूनिट
45. औद्योगिक शहरी क्षेत्र नया और बिस्तारित।	5000 आवासीय यूनिट

अनुसूची-3

पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के लिए विशेषज्ञ, समितियों की संरचना

निम्नलिखित से मिलकर बने प्रत्येक विकास क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों से गठित विशेषज्ञ समितियाँ, केन्द्रीय या राज्य स्तर पर विकास सेक्टरों का निर्धारण और निर्धारण करेंगी :

1. सुसंगत विकास सेक्टर में ऐसा प्रतिभाशाली और अनुभव परितस्थितिकी विज्ञानी या पर्यावरणीय विज्ञानी या तकनीकी श्रुतिक जिम्मेदारिता रणीक संरक्षण और किए जाने योग्य विकास में अभिरुचि प्रवर्धित की हो—अवयव।

विशेषज्ञ सदस्य

ऐसे सदस्य जो सुसंगत क्षेत्र में एस. टेक/पी.एच.डी. हैं और जिनके पास सुसंगत विकास सेक्टर में पर्यावरणीय प्रभाव में कम से कम 8 वर्ष के अनुभव के साथ दीर्घकालीन अनुभव है :

2. परितस्थितिकी तंत्र प्रबंधक साथ ही तंत्र प्रबंध और प्रतिक्रिया अनुभव
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण
4. जल प्रदूषण नियंत्रण
5. वनस्पति/प्राणी संवर्धन और प्रबंध
6. जल संसाधन प्रबंध
7. भूमि उपयोग योजना/निष्पेक्षित भूमि का जैव उद्धार
8. जलीय जीवतन्त्रा संरक्षण और सुरक्षण

9-10 परिस्थितिकी विज्ञानी (2)

11 निर्वाचित परियोजना के पुनर्वास के अनुभव के साथ सामाजिक वैज्ञानिक

12 अध्यात्म और परियोजना आगम की परीक्षा भूमि का विशेषज्ञ

13-14. सुसंगत विकास सेक्टर में विषय क्षेत्र विशेषज्ञ (2)

15 गैर सरकारी संस्थाएँ पर्यावरणीय अनुरोध समूह का प्रतिनिधि

16 केन्द्र/राज्य में प्रभाव निर्धारण अभिकरण का प्रतिनिधि।

सहस्र-सचिव

टिप्पणी:—विशेषज्ञ, अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे मिथ्या उनके जिन्हें विविष्ट रूप से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है।

उपस्थ

प्रारम्भ प्रण

1. (क) स्थापित परियोजना का नाम और पता

(ख) परियोजना की अवस्थिति

(ग) स्थान का नाम

(घ) जलवा, नदी/नाल

(ङ) अक्षांश/रेखांश

(च) समीपतम विमान पत्तन/रेलवे स्टेशन

(ज) परिचित या कुकर्मिक स्थल और पर्यावरित स्थल के लिए कारण

2. परियोजना के उद्देश्य

(क) भूमि उपयोग

(ख) भूमि

(ग) जल भूमि और वनस्पति का धनत्व

(घ) अभ्य (निर्माणादि करे)

(ङ) (1) आवाह में भूमि उपयोग/प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. की परिधि के भीतर

(2) अवस्था, अभिव्यक्ति और तुलना की वृद्धि हुए क्षेत्र की स्थलाकृति

(3) धारण की सुधेयता

(ग) 10 कि.मी. की परिधि में विद्यमान प्रदूषण स्रोत और उनका वायु, जल तथा भूमि की गुणवत्ता पर प्रभाव।

(ज) समीपतम राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/आरक्षित/जीवमंडल/संस्मारक/परंपरास्थल/आरक्षित वन की दूरी।

(ङ) खदानों/उद्यार क्षेत्रों के लिए पुनर्वास योजना

(च) हरित पट्टा योजना

(छ) प्रतिकरात्मक वनरोपण योजना

3. जलवायु और वायु की गुणवत्ता

(क) स्थल पर पवनचाल

(ख) वार्षिक अधिकतम/न्यूनतम/माध्यमिक तापमान

(ग) प्रतिशतमान दो आयतन

(घ) चक्रवात/टॉर्नेडो/बृष्टि प्रस्फोट की आवृत्ति

- (क) परिवेश वायु गुणवत्ता आंकड़ा
- (ख) परियोजना से उत्सर्जित एस पी एस गैसों (सी ओ, सी ओ₂, एस ओ₂, एस ओ₃, सी एच एस आदि) की प्रकृति और मात्रा
- 5 (क) जल-संतुलन स्थल
- (ख) शुष्क मौसम जल उपलब्धता, जल आपेक्षा
- (ग) प्रतियोगी उपयोक्ताओं (नदी, झील, भूमि आदि प्रदाय) से टेप किया जाने वाला स्त्रोत
- (घ) जल गुणवत्ता
- (ङ) गत 15 वर्षों में भूमिगत-जल में संश्लेषित परिवर्तन और वर्तमान परिवर्तन तथा निष्कर्षण दरें
- (च) (1) उपचार धाराओं के साथ छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा
- (2) अपशिष्ट जल के व्ययन के पठने और बाड़ में बाहरी स्थान पर जल की गुणवत्ता की मात्रा
- (छ) (1) आवश्यक आवाह उपचार योजना के साथ कुंड जल की गुणवत्ता के धोरें
- (2) प्रभाव क्षेत्र विकास योजना
- 6 डोस अपशिष्ट
- (क) निस्तारण व्ययन के लिए जनित डोस अपशिष्टों की प्रकृति और मात्रा
- (ख) वायु, जल और भूमि के आघात होने वाले प्रदूषण के निवारण के लिए डोस अपशिष्ट व्ययन रीति
- 7 शोर और कंपन
- (क) शोर और कंपन के स्त्रोत
- (ख) परिवेश शोर स्तर
- (ग) प्रस्तावित शोर और कंपन नियंत्रण उपाय
- (घ) नियंत्रण उपायों में अवतल समस्या, यदि कोई हो
- 8 प्रदाय के स्त्रोत को धरात हूँ।" याम्ब अपेक्षा; यदि स्वैच्छिक धर्मित एका का प्रस्ताव हो, तो पूर्ण पर्यावरणीय ध्येरे अलग से के
- 9 ध्योरों के साथ धधनियोजित किया जाने वाला अधकतम ध्रम बल
- कार्यबल की धारमिक छानबीन के माध्यम से स्वास्थ्य प्रास्थिति--ध्रमकों और धधचारिबन्ध, धोलो की धेल में अपशिष्ट/भूमि से उत्पन्न रोगों के कारण स्थानिक स्वास्थ्य समस्याएं प्रस्तावित स्वास्थ्य पद्धति
- 10 (क) ध्रमों की संख्या और जनसंख्या उपदर्शित की जाए
- (ख) पुनर्वासि मास्टर प्लान
- 11 सकट प्रबंध योजना के साथ जीविक निधारण रिपोर्ट
- 12 (क) परियोजना की निस्तृत रिपोर्टें
- (ख) पर्यावरणीय प्रभाव निधारण रिपोर्टें
- (ग) पर्यावरणीय प्रबंध योजना
- 13 पर्यावरणीय प्रबंध कक्षा का निस्तृत ध्येरा
- 14 वायु और जल की गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का स्थापित किया जाना

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, 29th January, 1991

[Under Section 3(1) and Section 3(2) (v) of Environment (Protection) Act, 1986 and Rule 5(3)(a) of Environment (Protection) Rules, 1986 on Environment Clearance].

Whereas considerable adverse environment impact has been caused due to degradation of the environment with excessive soil erosion and water and air pollution on account of certain development activities, thereby engendering not only the destruction of natural resources like forests, mangroves, wetlands, rivers, lakes, genepool reserves, and vegetation cover which is fast dwindling in large parts of the country, but also affecting the health and very survival of living beings—both animal and human;

And whereas it is necessary to protect and improve the quality of environment by controlling pollution of air, water and soil along with biotic pressure on natural resources, which is so intense that our natural biological and genetic wealth is threatened with severe damage;

And whereas certain development projects should be carried on within the carrying capacity of the ecosystem through judicious location beyond defined distances from eco-systems which will otherwise come under stress, so as to ensure that developmental activity takes place in harmony with the environment and improvement thereof;

And whereas the aforesaid goals can be achieved only by careful assessment of a project proposed to be located in any area, on the basis of an environmental Impact Assessment of each project and the necessary Environment Management Plan for the prevention, elimination or mitigation of the adverse impacts, right from the inception stage of the project;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby directs that on and from the date of the final publication of this notification under clause (d) of Sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the expansion or modernisation of any existing industry or new projects listed in Schedule I or Schedule II shall not be undertaken in any part of India, unless it has been accorded environmental clearance by the Central Government or, as the case may be, the State Government concerned in accordance with the procedure hereinafter specified in this notification.

2. Notwithstanding anything contained in Schedule-II, any project proposed to be located within 10 kilometers of the boundary of reserved forests, or a designated ecologically sensitive area, or within 25 kilometers of the boundary of national park or sanctuary, will require environmental clearance from the Central Government.

3. Notwithstanding anything contained in Schedules I and II, the Central Government in the Ministry or environment and Forests may review the environmental clearance given to any project by any State Government if :

- (a) written representation is received by that Ministry against such clearance from the affected parties or
- (b) it is prima facie evident that environmental imperatives and norms specified by that Ministry have been ignored by the State Government concerned while giving such clearance.

4. Procedure for seeking environment clearance of projects.—(I) Any person who desires to undertake any project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project listed in Schedules I and II shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, New Delhi, where environmental clearance is required from the Central Government, or to Environment Secretary of the State Government concerned, where the environmental clearance is required from the State Government. The application shall be made in the proforma appended to this notification and shall be accompanied by a detailed project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report and an Environment Management Plan prepared in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(II) In case of the following site-specified projects :

- (a) mining;
- (b) pit-head thermal power stations;
- (c) hydro-electric power projects; and
- (d) Multi-purpose river valley projects.

a preliminary site clearance will be required from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests before initiating any investigations involving cutting of trees, drilling, digging or construction of any sort temporary or permanent.

The said site clearance will be granted for the sanctioned capacity and will be valid for a period of 5 years for commencing the construction.

(III) (a) The detailed project report submitted with the application shall be evaluated and assessed by the Impact Assessment Agency of the Central Government or, as the case may be, of the State Government in consultation with a committee of Experts, having a composition as specified in Schedule III to this notification.

The said Committee of Experts will have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to, during, or after the commencement of the operations relating to the project.

(c) The Impact Assessment Agency will prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data furnished by the project authorities supplemented by data collected during visits to the site or factory, interaction with affected population and environmental groups. The recommendations and the conditions subject to which environmental clearance is given may be made available to concerned parties. The assessment shall be completed within a period of 3 months on receipt of the requisite documents and data from the project authorities.

(IV) In order to enable the Impact Assessment Agency concerned to monitor the effective implementation of the recommendations and conditions subject to which the environmental clearance has been given, the project authorities concerned shall submit a half-yearly report to the concerned agency.

5. Any person interested in filing any objection against the proposed directions contained in this notification, may do so in writing to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi within 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. Z-12013/4/89-IA-I]

R. RAJAMANI, Secy. (EKF)

SCHEDULE-I

LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Atomic Power
2. Thermal Power

3. Multi-purpose River Valley Projects
4. Ports, Harbours and Airports
5. Railway lines (involving acquisition of non-railway land)
6. Refineries
7. Fertilizers
8. Pesticides and Insecticides
9. Petrochemicals
10. Explosives and Accessories
11. Drugs and Pharmaceuticals (except formulations)
12. Production of Plastics
13. Rubber-Synthetic
14. Asbestos and asbestos products
15. Sodium or Potassium Cyanide
16. Primary metallurgical industries (Zinc, Lead, Copper Aluminium and Steel)
17. Integrated Steel Plants
18. Tyres/tubes of trucks, jeeps, cars and other heavy vehicles.
19. Alkalis (Na OH)
20. Integrated Paint Complex.
21. Man-made fibres (Synthetics & semi-Synthetics, Rayon, Nylon and Polyester)
22. Storage batteries with lead processing
23. Incineration plants for hazardous waste and chlorinated hydrocarbons.
24. All projects with threshold criteria above those specified in Schedule-II

SCHEDULE-II

LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE STATE GOVERNMENT

(Subject to the provisions of para 2 of the notification)

Nature of Projects	Threshold Criteria (if any)
1. Ceramics	
2. Coal Washery	
3. Briquetting	
4. Carbonising Plant	
5. Engineering (Tubings, Castings, Rolling Mills)	
6. Refractories	
7. Pipelines (RCC, Steel, Seamless)	
8. Calcium Carbide	
9. Carbon Black	
10. Reprocessing Lubricating Oil	
11. Glass	
12. Drugs and Pharmaceuticals (Formulations)	

13. Electroplating	
14. Storage Batteries (non-lead processing)	
15. Alkalis (Na_2CO_3 and CaCO_3)	
16. Plastics Processing (HDPE, LLDPE, LDPE, PVC, PP, etc.)	
17. Tyres/Tubing of two-wheelers and cycle rickshaws	
18. Retreading of all types of tyres	
19. Paints (Varnish, Coal Tar Chemicals, Pigments)	
20. Dye Single Industry	
21. Soaps and detergents	
22. Food Processing (Meat, Fish, Animal Products)	
23. Milk Processing	
24. Paper Products	
25. Incineration Plants for non-hazardous waste	
26. Hydro-electric power	PRODUCTION CAPACITY
(a) New projects	Upto 10 MW
(b) All power houses to be located on existing canal falls or existing dams with already embedded penstocks.	Upto 10 MW
27. Cement	Upto 200 TPD
28. Steel Plants	Upto 50,000 TPA
29. Leather Tannery	Upto 5,000 Skins PD
30. Distilleries	Upto 150 KLD
31. Sugar	Upto 4,000 TPD cane
32. Textile	Upto 500 Mts/d
33. Pulp, Paper & Newsprint	Upto 33,000 TPA
34. Dye Intermediates	Upto 5 TPD
35. Thermosets Phenol and Urea formaldehyde	Upto 5,000 TPD
36. Acids	Upto 500 TPD
37. Vegetable Oil Processing	Upto 500 TPD
38. Foundries	CAPITAL COST
39. Communications	Upto Rs. 20 crores
40. Tourism and other projects within 1 Km. of HTL of sea, or at locations with an elevation of more than 1000 mts.	Upto Rs. 20 crores
	Upto Rs. 5 crores
41. Irrigation	AREA
42. Mining	Upto 2000 Hectare Command
43. Roads (in Himalayas or involving forest land)	Upto 5 hectare lease
44. Industrial Estates	Upto 5 kms. length
45. Industrial Township (New & Expansion)	Upto 100 units
	Upto 5000 dwelling units

SCHEDULE III

COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEES FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT.

The evaluation and assessment of development projects at the Central or State level will be undertaken by Expert Committees consisting of technical experts in each development section constituted as under :

1. An outstanding and experienced ecologist or environmentalist or technical professional in the relevant development sector having demonstrated interest in Environment Conservation and sustainable development.

EXPERT MEMBERS

Members with M. Teih./Ph. D. in the relevant field and long experience including at least 8 years experience in environmental management in relevant sectors :

- 2¹ Eco-system Manager with Systems Management & Modelling Experience.
3. Air Pollution Control.
4. Water Pollution Control.
5. Flora/Fauna Survey & Management
6. Water Resources Management
7. Land Use Planning/Biological reclamation of degraded lands.
8. Conservation & Protection of Aquatic Life.
- 9.10. Ecologists (2)
11. Social Scientist with experience of rehabilitation of project oustees
12. Specialist with background of economics and project appraisal.
- 13-14. Subject area Specialists in relevant development sector (2).
15. Representative of NGO/Environmental Action Groups.
16. Representative of Impact Assessment agency at Centre/State. . .Member Secretary.

Note : Experts inducted will serve in their individual capacities except those specifically nominated as representatives.

ANNEXURE

APPLICATION FORM

- (1. (a) Name & Address of the project proposed :
- (b) Location of the projects :
Name of the place :
District, Tehsil :
Latitude/Longitude .

Nearest Airport/Railway Stn.:

- (c) Alternate sites examined and the reasons for the site proposed :
2. Objectives of the project :
3. (a) Land Requirement :
Agriculture land :
Forest land and Density of vegetation.
Other (specify) :
- (b) (i) Landuse in the Catchment/within 10 Kms. radius of the proposed site.
(ii) Topography of the area indicating gradient, aspects & altitude.
(iii) Vulnerability to erosion.
- (c) Pollution sources existing in the 10 Km. radius and their impact on quality of air, water & land:
- (d) Distance of the nearest National Park/Sanctuary/Biosphere Reserve/Monuments/heritage site/Reserve Forest :
- (e) Rehabilitation plan for quarries/borrow areas
- (f) Green belt Plan :
- (g) Compensatory afforestation plan :
4. Climate & Air Quality :
(a) Windrose at site
(b) Max/Min./Mean annual temperature
(c) Incidence of inversion :
(d) Frequency of cyclones, tornadoes/cloud bursts:
(e) Ambient air quality data
(f) Nature & concentration of emission of SPM Gases (CO, CO₂, SO₂, NO₂, CH₄ etc) from the project:
(a) Water balance site :
(b) Lean season water availability;
Water Requirement :
(c) source to be tapped with competing users (River, lake, Ground, Public Supply)
(d) Water quality :
(e) Changes observed in ground water in the last 15 years and present changing & extraction details :
(f) (i) Quantum of waste water to be released with treatment details
(iii) Quantum of quality of water in the receiving body before and after disposal of Solid Wastes :
(g) (i) Details of reservoir water quality with necessary Catchment Treatment Plan;
(ii) Command Area Development Plan:
6. Solid Wastes :
(a) Nature & quantity of solid wastes generated to be disposed :

- (b) Solid waste disposal method to prevent further pollution of air, water and land:
7. Noise & Vibrations :
- (a) Sources of noise & vibrations :
- (b) Ambient noise level :
- (c) Noise & Vibration control measures proposed:
- (d) Subsidence problem if any with control measures :
8. Power requirement indicating source of supply; complete environmental details to be furnished separately, if captive power unit proposed:
9. Peak labour force to be deployed giving details of :
- Health status through preliminary screening of workforce—labour & staff both;
- Endemic health problems in the area due to waste/soil borne diseases;
- Health care system proposed;
10. (a) Number of villages & population to be displaced :
- (b) Rehabilitation Master Plan:
11. Risk assessment report along with Disaster Management Plan:
12. (a) Detailed Project Report :
 (b) Environmental Impact Assessment Report :
 (c) Environmental Management Plan.
- Prepared as per
Guidelines of
MLF.
13. Details of Environmental Management Cell.
14. Details of air & water quality monitoring stations to be set-up.

